कामये दुःखतप्तानाम्।
प्राणिनाम् आर्तिनाशनम्॥

जागृति

वर्ष: 65 अंक: 3 मुम्बई फरवरी 2021

श्री नितिन गडकरी द्वारा प्रकृति की गोद में "अष्ट लाभ" के साथ 'खादी प्राकृतिक पेंट' का शुभारंभ

खादी और ग्रामोद्योग आयोग की औद्योगिकीकरण विषयक मासिक पत्रिका
खादी और ग्रामोद्योग आयोग

जागृति

वर्ष: 65 अंक-3 मुम्बई फरवरी 2021

सम्पादकीय मण्डल

अध्यक्ष

श्रीमती प्रीता वर्मा

संपादक

एम. राजन बाबू

सह संपादक

स्मिता जी. नायर

उप संपादक

सुबोध कुमार

वरिष्ठ हिंदी अनुवाद अधिकारी

सरस्वती खनका

डिजाईन व पृष्ठसज्जा

सुबोध कुमार

दिलीप पालकर

प्रचार, फ़िल्म एवं लोक शिक्षण
कार्यक्रम निदेशालय द्वारा
खादी और ग्रामोद्योग आयोग,
ग्रामोदय, 3 इर्ला रोड, विले पार्ले (पश्चिम),
मुंबई -400056 के लिए ई-प्रकाशित
ईमेल: kvicpub@gmail.com
वेबसाइट: www.kvic.org.in

आवश्यक नहीं कि पत्रिका में प्रकाशित लेखों तथा विचारों से खादी और ग्रामोद्योग आयोग अथवा संपादक सहमत हों

इस अंक में.....

समाचार सार 03-26

श्री नितिन गडकरी ने प्रकृति की गोद में 'अष्ट लाभ' के साथ 'खादी प्राकृतिक पेंट'.....

आयोग ने असम की सबसे पुरानी खादी संस्था को पुनर्जीवित किया .....

आदिवासी छात्रों को पर्यावरण के अनुकूल खादी यूनिफार्म पहनाने.....

श्री गडकरी द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए विपणन के नये रास्ते और.....

माननीय एमएसएमई मंत्री द्वारा कनॉट प्लेस, नई दिल्ली में नए ग्रामोद्योग उत्पादों.....

'टेराकोटा कुम्हारी केन्द्र, भद्रावती' के लिए 10 करोड़ रुपये की सहायता.....

लखनऊ में मुख्यमंत्री द्वारा "हुनर हाट" का उद्घाटन.....

एमएसएमई मंत्री द्वारा 27 जनवरी, 2021 को केरल के त्रिशूर में फर्नीचर क्लस्टर का.....

ई-मार्केटिंग के जरिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म केवीआईसी द्वारा किए गए बदलाव.....

आयोग ने भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर.....

आयोग द्वारा स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने के लिए पश्चिम बंगाल में 2250 कारीगरों .....

कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान केवीआईसी को रेलवे के 49 करोड़ रुपये की खरीद के ऑर्डर से खादी कारीगरों को बड़ा प्रोत्साहन.....

लखनऊ में आयोग के अध्यक्ष द्वारा एक बैग निर्माण - पीएमईजीपी इकाई का उद्घाटन.....

आयोग के अध्यक्ष ने भेलसर में एक पीएमईजीपी इकाई-जनता बेकरी का उद्घाटन.....

खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने 72 वां गणतंत्र दिवस मनाया.....

महबूबनगर में कुम्हारी चाक के साथ प्रमाण-पत्र का वितरण.....

आयोग द्वारा खादी प्राकृतिक पेंट बनाने पर प्रशिक्षण हेतु नवोदित उद्यमियों के प्रथम बैच.....

फुटवियर बनाने हेतु प्रशिक्षण एवं प्रमाण पत्र का वितरण.....

कार्यशालाएं.....

उत्तर प्रदेश राज्य में पीएमईजीपी योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने हेतु लखनऊ में.....

राज्य कार्यालय, देहरादून में स्वच्छता पखवाड़ा.....

मीडिया कवरेज..... 27

सोशल मीडिया एवं ई-पेपर .....

श्री नितिन गडकरी ने प्रकृति की गोद में 'अष्ट लाभ' के साथ 'खादी प्राकृतिक पेंट' का शुभारंभ किया

दिल्ली, 12 जनवरी, 2021: **सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री नितिन गडकरी ने प्रकृति की गोद में "अष्ट लाभ" के साथ इनोवेटिव खादी प्राकृतिक पेंट लॉन्च किया।**

गाय के गोबर से घर लीपने की सदियों पुरानी भारतीय परंपरा को सुदृढ़ करते हुए खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने खादी प्राकृतिक पेंट विकसित किया है, भारत में अपनी तरह का यह पहला पेंट है जो गोबर से आठ फायदे या अष्ट लाभ के साथ बनाया जाता है यह पर्यावरण के अनुकूल और लागत प्रभावी के साथ अद्वितीय एवं अभिनव उत्पाद है जिसे आज सूक्ष्म, लघु एवं माध्यम उद्यम मंत्री श्री नितिन गडकरी द्वारा दिल्ली स्थित अपने आवास लॉन्च किया गया।

इस अवसर पर माननीय केंद्रीय मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री गिरिराज सिंह; माननीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री श्री प्रताप चन्द्र सारंगी और केवीआईसी के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना उपस्थित थे।

पेंट लॉन्च के दौरान श्री गडकरी ने कहा कि इनोवेटिव खादी पेंट में 6000

Khadi India Prakritik Paint
(INDIA'S FIRST COW DUNG PAINT)

करोड़ रुपये के बाजार में विकसित होने और 10 लाख नए रोजगार सृजित करने की क्षमता है जो देश की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बदल देगा।

श्री गडकरी ने कहा, "भारत में अधिकतम लोगों को खादी प्राकृतिक पेंट के तकनीकी ज्ञान को साझा करने के लिए एक नीति तैयार की जाएगी। केवीआईसी नए उद्यमियों को तकनीकी प्रशिक्षण देगा, जो गोबर से पेंट का निर्माण करके लाभान्वित हो सकते हैं। देश भर में हजारों प्राकृत रंग निर्माण इकाइयाँ स्थापित की जा सकती हैं जो स्थानीय विनिर्माण और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देंगी।"

उन्होंने कहा कि, "गोबर के थोक उपयोग से किसानों को आर्थिक लाभ होगा जो उन्हें बाजार में गायों को बेचने से भी रोकेंगा जिससे गोहत्या पर लगाम लगेगी। हम अर्थव्यवस्था के माध्यम से गोहत्या बंद करेंगे, न कि कानून के माध्यम से।"

इस अवसर पर बोलते हुए श्री गिरिराज सिंह ने प्रमुख पेंट निर्माण कंपनियों से अपील की कि वे एक इको-फ्रेंडली उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए केवीआईसी से गाय के गोबर से पेंट बनाने के लिए तकनीकी ज्ञान को जानें जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। श्री सिंह ने कहा, "गोबर के प्राकृतिक लाभ इस खादी प्राकृतिक पेंट को घरों के लिए एक

आदर्श प्रतिरक्षा बनाते हैं।"

श्री प्रताप चंद्र सारंगी ने इस अवसर पर कहा कि "वैदिक विज्ञान" या प्राचीन प्रथाओं एवं आधुनिक विज्ञान के मेल से खादी प्राकृतिक पेंट बनाया गया है।"

इस अवसर पर केवीआईसी के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि खादी प्राकृतिक पेंट केवल एक उत्पाद नहीं, बल्कि भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में तेजी लाने का एक उपकरण है। "गोबर पेंट विकसित करने का मुख्य उद्देश्य रोजगार सृजन है जो खादी का मूल आधार है। श्री सक्सेना ने कहा कि यह पेंट वैज्ञानिक परीक्षण वाले आधुनिक उत्पाद में सदियों पुरानी प्रथाओं का पुनर्निमाण है।"

खादी प्राकृतिक पेंट का उत्पादन माननीय प्रधान मंत्री द्वारा किसानों की आय बढ़ाने के दृष्टिकोण को ध्यान मे रखकर किया गया है। साथ ही, यह पेंट विनिर्माण के क्षेत्र में हजारों नई नौकरियों का सृजन करेगा क्योंकि केवीआईसी प्रौद्योगिकी साझा करेगा और प्राकृतिक पेंट के निर्माण के लिए प्रशिक्षण भी प्रदान करेगा। वर्तमान में, जयपुर में केवीआईसी के कुमारप्पा नेशनल हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट में प्राकृतिक पेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में 500 लीटर पेंट का उत्पादन करने की दैनिक क्षमता है जो 10 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है।

वाटरप्रूफ और वॉशेबल होने के अलावा, खादी प्रकृतिक पेंट में गाय के गोबर के प्राकृतिक लाभ जैसे एंटी-बैक्टीरियल, एंटी-फंगल और प्राकृतिक थर्मल इन्सुलेशन गुण होते हैं। यह पेंट इको-फ्रेंडली, नॉन-टॉक्सिक, गंध रहित और लागत प्रभावी है। इमल्शन पेंट- बीआईएस 15489: 2013 तथा डिस्टेंपर पेंट- BIS 428: 2013 मानकों के अनुरूप है।

इस श्रेणी के अन्य पेंट्स की तुलना में खादी प्राकृतिक पेंट 50 प्रतिशत तक किफायती हैं।

खादी प्राकृतिक पेंट -डिस्टेंपर पेंट और प्लास्टिक इमल्शन पेंट दो रूपों में उपलब्ध होगा। गाय का गोबर इस पेंट का मुख्य कच्चा माल है जो देश भर में आसानी से और प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इसलिए, पेंट के लिए कच्चे माल की वर्ष भर की उपलब्धता सुनिश्चित है जो किसानों और गौशालाओं के लिए प्रति पशु 30,000 रुपये तक की अतिरिक्त आय का सृजन करेगा।

आयोग ने असम की सबसे पुरानी खादी संस्था को पुनर्जीवित किया जिसे बोडो विद्रोहियों ने 30 वर्ष पहले जला दिया था

असम, 28.01.2021: असम के सबसे पुराने खादी संस्थाओं में से एक, जो 30 वर्षों से बोडो विद्रोह के चलते बर्बाद रहा, उसे खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ने नई जिंदगी दी है। असम के बक्सा जिले के कावली गांव में इस खादी उद्योग जिसे 1989 में बोडो विद्रोहियों द्वारा जला दिया गया था, उसे केवीआईसी ने सिल्क रीलिंग सेंटर के रूप में पुनर्जीवित किया गया है। फरवरी के दूसरे सप्ताह में 15 महिला कारीगरों और 5 अन्य कर्मचारियों के साथ यहां कताई और बुनाई की गतिविधियां फिर से शुरू होंगी।

1962 में चीन के आक्रमण के बाद अरुणाचल प्रदेश से असम में स्थानांतरित हुए तामुलपुर आंचलिक ग्रामदान संघ नामक खादी संस्था द्वारा इसका निर्माण किया गया था। शुरुआत में सरसों के तेल का उत्पादन यहां शुरू हुआ था और 1970 से यहां कताई और बुनाई गतिविधियों ने भी 50 कारीगर परिवारों को यहां आजीविका प्रदान करना शुरू कर दिया था। मगर त्रासदी तब हुई जब 1989 में इस संस्था को चरमपंथियों द्वारा जला दिया गया और तब से यह बंद रही।

केवीआईसी के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि इस खादी संस्था के पुनरुद्धार ने ऐतिहासिक महत्व ग्रहण किया है और खादी गतिविधियों को फिर से शुरू करने से यहां के स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा, "शुरुआत में केवीआईसी असम की एरी सिल्क की रीलिंग के लिए इकाई को विकसित करेगा। भविष्य में अन्य खादी गतिविधियों जैसे ग्रामोद्योग उत्पादों का निर्माण भी शुरू किया जाएगा। यह केंद्र स्थानीय कारीगरों के लिए एक प्रमुख रोजगार सृजन का काम करेगा। यह पहल खादी के मुख्य गांधीवादी सिद्धांत 'ग्रामीण पुनरुत्थान' से जुड़ी है जो माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण - सबका साथ, सबका विकास के अनुरूप है।

यह खादी संस्था गुवाहाटी से 90 किमी दूर स्थित है। केवीआईसी से वित्तीय सहायता के साथ इसे पुन: कार्यशील बनाया जा रहा है जिसके पीछे मकसद खादी कारीगरों को बेहतर कार्यशील स्थिति प्रदान करना है जिससे अंततः उनकी उत्पादकता में सुधार होगा। हाल के वर्षों में केवीआईसी ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, असम, ओडिशा और तमिलनाडु जैसे राज्यों में कई ऐसे खादी संस्थानों को पुनर्जीवित किया है जो कई दशकों से खराब पड़े हुए थे।

आदिवासी छात्रों को पर्यावरण के अनुकूल खादी यूनिफार्म पहनाने;
आदिवासी युवाओं को पीएमईजीपी प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

नई दिल्ली, 19.01.2021:खादी और ग्रामोद्योग आयोग और जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने आदिवासी छात्रों के लिए खादी कपड़े खरीदने और जनजातीय क्षेत्र में व्यापक रोजगार सृजन के लिए समझौता किया। माननीय एमएसएमई मंत्री श्री नितिन गडकरी और जनजातीय मामलों के माननीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा की उपस्थिति में इससे संबंधित दो ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। यह पहल माननीय प्रधान मंत्री के " आत्मनिर्भर भारत " के आह्वान को संबल देने के लिए है, जोकि खादी कारीगरों और देश के आदिवासी युवाओं को स्वरोजगार के माध्यम से मजबूत बनाने के उद्देश्य से की गई हैं।

पहले एमओयू के अंतर्गत, केवीआईसी जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे एकलव्य आवासीय विद्यालयों में छात्रों के लिए 2020-21 के दौरान 14.77 करोड़ रुपये के 6 लाख मीटर से अधिक के खादी वस्त्र की आपूर्ति करेगा। सरकार हर साल एकलव्य स्कूलों की संख्या बढ़ाएगी ; खादी कपड़े की खरीद की मात्रा भी आनुपातिक रूप से बढ़ेगी और खादी सामग्री की खरीद मूल्य प्रति वर्ष 50 करोड़ रुपये हो जाएगी।

दूसरे एमओयू में, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम (NSTFDC) के तहत, जनजातीय मामलों के मंत्रालय की एक एजेंसी को भारत सरकार की प्रमुख योजना प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को लागू करने में केवीआईसी के सहभागी के रूप में शामिल किया गया है।

श्री गडकरी ने समझौतों को ऐतिहासिक करार दिया और कहा कि इससे खादी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए केवीआईसी द्वारा किये जा रहे प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा और आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने के लिए स्वरोजगार का सृजन होगा। उन्होंने कहा कि "केवीआईसी और जनजातीय मामलों के मंत्रालय को भारत के प्रत्येक गाँव में 25 रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखना चाहिए, जिसके लिए एमएसएमई मंत्रालय धनराशि प्रदान करेगा। यह हमें ग्रामीण पुनरुत्थान या ग्रामोदय के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। श्री गडकरी ने कहा कि देश के आदिवासी युवा मधुमक्खी पालन, शहद प्रसंस्करण, गोबर पेंट का निर्माण, अगरबत्ती

निर्माण और बांस उत्पादन जैसी गतिविधियों से जुड़ सकते हैं जो आर्थिक रूप से लाभकारी हैं।

माननीय आदिवासी मामलों के मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि समझौता ज्ञापन से आदिवासियों को विभिन्न उत्पादन गतिविधियों में संलग्न करके और स्वरोजगार के अवसर पैदा होंगे। श्री मुंडा ने कहा, "जनजातीय क्षेत्रों में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना और स्थानीय उत्पादन को बढ़ाना न केवल भारत के विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करेगा, बल्कि वैश्विक बाज़ार का मार्ग भी निर्माण करेगा।"

केवीआईसी के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि हनी मिशन और कुम्हार सशक्तिकरण योजना जैसी प्रमुख योजनाओं के माध्यम से खादी पहले से ही देश भर में आदिवासियों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए काम कर रही है और जनजातीय मामलों के मंत्रालय के साथ इस समझौते से विकास की गति तेज होगी।

"गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और असम जैसे राज्यों में हजारों आदिवासी युवाओं और महिलाओं को रोजगार सृजन योजनाओं जैसे हनी मिशन और कुम्हार सशक्तिकरण योजना से जोड़ा गया है। कई आदिवासी खादी के कपड़े के उत्पादन से भी जुड़े हैं। मुझे उम्मीद है कि इस एमओयू के बाद पीएमईजीपी के माध्यम से विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में आदिवासी युवाओं की भागीदारी बढ़ेगी।

केवीआईसी के अध्यक्ष ने कहा कि आदिवासी छात्रों के लिए खादी के कपड़े की थोक खरीद के समझौते से खादी कारीगरों को अधिक रोजगार और उच्च आय के अर्जन में फायदा होगा। उन्होंने कहा कि इन आपूर्ति के साथ, आदिवासी छात्रों को खादी वस्त्र से बने सबसे अधिक पर्यावरण के अनुकूल और आरामदायक यूनिफॉर्म पहनने को मिलेगी। भविष्य में भी, केवीआईसी और अधिक खादी उत्पादों की आपूर्ति करने की योजना बना रहा है, जैसे कि छात्रों के लिए बिस्तर, तौलिया, दरियाँ इत्यादि।

श्री गडकरी द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए विपणन के नये रास्ते और निर्यात की नयी संभावनाओं की खोज करने का आह्वान

नई दिल्ली, 25.01.2021: केन्द्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कहा है कि विपणन के रास्ते और निर्यात की नयी संभावनाओं की खोज करके भारत के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के योगदान को अगले 5 वर्षों में 30% से बढ़ाकर 40% तक बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ग्रामोद्योग क्षेत्र, जिसमें 5 लाख करोड़ रुपये का वार्षिक कारोबार का लक्ष्य प्राप्त करने की क्षमता है, को सशक्त बनाकर लाखों रोजगार सृजित किये जा सकते हैं।

श्री गडकरी ने नई दिल्ली के कनॉट प्लेस में खादी इंडिया के प्रमुख बिक्री - केन्द्र का दौरा किया और उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड की महिला कारीगरों द्वारा बनाए गए कई ग्रामोद्योग उत्पादों को लॉन्च किया। श्री गडकरी ने बिक्री – केन्द्र में कई स्टालों का जायजा लिया और विविध उत्पाद रेंज के लिए खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) की सराहना की, जिसने खादी के कारीगरों के लिए आजीविका का सृजन किया।

एमएसएमई मंत्री द्वारा कनॉट प्लेस, नई दिल्ली में नए ग्रामोद्योग उत्पादों का शुभारंभ

नई दिल्ली, 25.01.2021: 'पंडित दीनदयाल उपाध्याय विज्ञान ग्राम संकुल योजना' के अंतर्गत बने विभिन्न उत्पादों को आज संकुल योजना के अध्यक्ष डॉ. महेश शर्मा जी और खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना जी की उपस्थिति में लॉन्च किया।

इस योजना के तहत बनाए जा रहे सस्ते और इको फ्रेंडली उत्पाद ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होंगे।

'टेराकोटा कुम्हारी केन्द्र, भद्रावती' के लिए 10 करोड़ रुपये की सहायता

केंद्रीय एमएसएमई मंत्री ने भद्रावती में आयोग द्वारा संचालित टेराकोटा कुम्हारी केन्द्र का दौरा किया

केंद्रीय एमएसएमई मंत्री श्री नितिन गडकरी ने भद्रावती में खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा संचालित टेराकोटा कुम्हारी केन्द्र को एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के रुप में स्थापित करने के लिए केन्द्र को अनुसंधान और विकास के लिए 10 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है। "यह संस्थान 1956 में स्थापित एक प्राचीन एक है और श्री गडकरी ने 21 जनवरी 2021 को टेराकोटा केंद्र का दौरा किया और केंद्र के कार्य पैटर्न के बारे में जानकारी ली।

हालांकि संस्थान ने आधुनिक विकास के अनुसार परिवर्तनों को नहीं अपनाया, लेकिन खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने कला और संस्कृति को जीवित रखा है। कला और संस्कृति के विकास के उद्देश्य से और गढ़चिरौली और चंद्रपुर जिलों में युवाओं और महिलाओं के लिए केवीआईसी द्वारा संचालित एमएसएमई की स्फूर्ति योजना के तहत रोजगार उत्पन्न करने के लिए इस संस्थान को 1.5 करोड़ राशि की मंजूरी दी गई है और इस वर्ष में यह काम पूरा हो जाएगा।"

भद्रावती में जल्द ही "गुणवत्ता आश्वासन, अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया जाएगा।"उन्होंने घोषणा की, कि जल्द ही यहां रेड क्ले पॉटरी का एक अंतरराष्ट्रीय केंद्र स्थापित किया जाएगा जिसके लिए केंद्र सरकार की ओर से रु 10 करोड़ दिया जाएगा, सह केंद्र अलग-अलग डिजाइन तैयार करने में मदद करेगा। कारीगरों को उनके गांवों में उद्यमिता शुरू करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए विकास योजना शुरू की गई है और भद्रावती का नाम अंतरराष्ट्रीय मानचित्र पर दिखाई देगा।

माननीय एमएसएमई मंत्री ने आगे इस केंद्र के लिए छात्रावास और भवन बनाने का निर्देश दिया। केंद्र द्वारा प्रशिक्षित कारीगरों की संख्या और इसके माध्यम से उत्पन्न रोजगार के आधार पर इसे आंका जाएगा। उन्होंने कहा कि जनता के प्रतिनिधि इसके विकास में मदद करेंगे।

इस अवसर पर केवीआईसी के मंडलीय निदेशक, संभागीय कार्यालय, नागपुर और कार्यक्रम निदेशक भी उपस्थित थे।

लखनऊ में मुख्यमंत्री द्वारा "हुनर हाट" का उद्घाटन

उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने 23 जनवरी, 2021 को लखनऊ में हुनर हाट का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के अवध शिल्पग्राम में दस्तकारों और शिल्पकारों के सामानों की बिक्री के लिए केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित 24वें हुनर हाट का उद्घाटन करते हुए कहा कि हमारा परंपरागत उद्यम ही आत्मनिर्भर और स्वावलंबी भारत का आधार है।

उन्होंने कहा, 'हम प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्पों को जरूर पूरा करेंगे।' उन्होंने बताया कि इस बार का हुनर हाट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें ओडीओपी (एक जिला-एक उत्पाद) को जोड़ा गया है।

इस अवसर पर माननीय केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी और खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना उपस्थित थे।

हुनर हाट पारंपरिक भारतीय शिल्पकारों की उत्कृष्ट कलात्मकता, कौशल और दृढ़ता को दर्शाता है, जो कि आत्मनिर्भर भारत के संवाहक हैं।

एमएसएमई मंत्री द्वारा 27 जनवरी, 2021 को केरल के त्रिशूर में फर्नीचर क्लस्टर का उद्घाटन

ई-मार्केटिंग के जरिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म केवीआईसी द्वारा किए गए बदलाव का प्रतीक बना

- यह पोर्टल भारतीय स्थानीय उत्पादों और उनके निर्माताओं को घरेलू बाज़ार के साथ-साथ वैश्विक बाज़ारों तक पहुंचने में मदद करेगा
- ऑनलाइन और बी2सी मॉडल से ग्राहकों तक पहुंचने का मंत्रालय और केवीआईसी का यह पहला प्रयास है
- कोविड महामारी के चलते प्रदर्शनी और मार्केटिंग पर लगे तमाम प्रतिबंधों के मद्देनज़र केवीआईसी ने ऑनलाइन बिक्री और ई-मार्केटिंग की दिशा में कदम बढ़ाए
- यह प्रयास प्रधानमंत्री के 'वोकल फॉर लोकल' आह्वान की दिशा में सकारात्मक कदम है

नई दिल्ली, 01.01.2021: नववर्ष की पूर्व संध्या पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ने खादी इंडिया की पहली आधिकारिक ई-कॉमर्स वेबसाइट- eKhadiIndia.com को शुरू किया । इस वेबसाइट पर उपलब्ध उत्पाद सूची (कैटलॉग) में घरेलू स्तर पर तैयार किए गए खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों की 500 से अधिक श्रेणी में 50,000 से ज़्यादा उत्पाद हैं।यह पोर्टल एक अनुकूल व्यवस्था का निर्माण कर प्रधानमंत्री के "आत्मनिर्भर भारत" के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में एमएसएमई को सक्षम बनाता है।

पोर्टल की प्रायोगिक शुरुआत के दौरान एमएसएमई के सचिव श्री ए.के. शर्मा ने बताया कि बुनकरों, कारीगरों, शिल्पकारों और किसानों का हित हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। इनके द्वारा बनाए गए पर्यावरण अनुकूल और प्रमाणिक

खादी और पारंपरिक ग्रामोद्योग उत्पाद भारत के लोगों के दिलों में हमेशा से बसे हुए हैं। अब ये सभी उत्पाद ग्राहकों से केवल एक क्लिक की दूरी पर उपलब्ध हैं। पोर्टल ग्राहकों की ज़रूरतों को पूरा करने के साथ लोगों के घरों तक उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। पिछले कुछ महीनों से हम कोविड महामारी की चुनौती से निपटने और सभी ज़रूरी प्रतिबंधों का पालन करते हुए अनुकूल व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे थे, ताकि खादी और ग्रामोद्योग के उत्पादों को ग्राहकों तक पहुंचाया जा सके। केवीआईसी का यह ई-कॉमर्स पोर्टल इस दिशा में किए गए हमारे प्रयासों का ही सकारात्मक परिणाम है।

इस वेबसाइट के लॉन्च कार्यक्रम के दौरान केवीआईसी के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने बताया कि ekhadiindia.comअपनी तरह का पहला सरकारी ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मज़बूत और आत्मनिर्भर बनाना है। पिछले कुछ सालों के दौरान खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों की मांग में लगातार वृद्धि हुई है, अकेले 2018-19 में 25 फीसदी की वृद्धि दर्ज़ की गई थी। केवीआईसी के अध्यक्ष ने बताया कि इस ई-कॉमर्स वेबसाइट का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक खादी इंडिया उत्पादों को नई पीढ़ी के उपभोक्ताओं के लिए आसानी से उपलब्ध कराना है।

इस वेबसाइट पर परिधान, किराने का सामान, सौंदर्य प्रसाधन, घर की सजावट का सामान, स्वास्थ्य संबंधी उत्पादों से लेकर उपहार जैसे हज़ारों उत्पाद उपलब्ध हैं। प्राकृतिक और स्थानीय उत्पादों के प्रति नई पीढ़ी की बढ़ती रुचि को ध्यान में रखते हुए केवीआईसी भारत के लोकप्रिय ब्रांड खादी के ई-कॉमर्स पोर्टल के माध्यम से इस पीढ़ी तक पहुंचने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यह पोर्टल उन युवाओं के लिए भी एक बेहतरीन सुविधा है, जो बाज़ार जाकर खरीदारी करने के बजाय ऑनलाइन शॉपिंग करना ज़्यादा पसंद करते हैं।

ekhadiindia.com वेबसाइट के कुछ मुख्य बिन्दु, जो इसे अन्य ई-कॉमर्स वेबसाइटों से अलग बनाते हैः-

(शेष पृष्ठ 20.....पर)

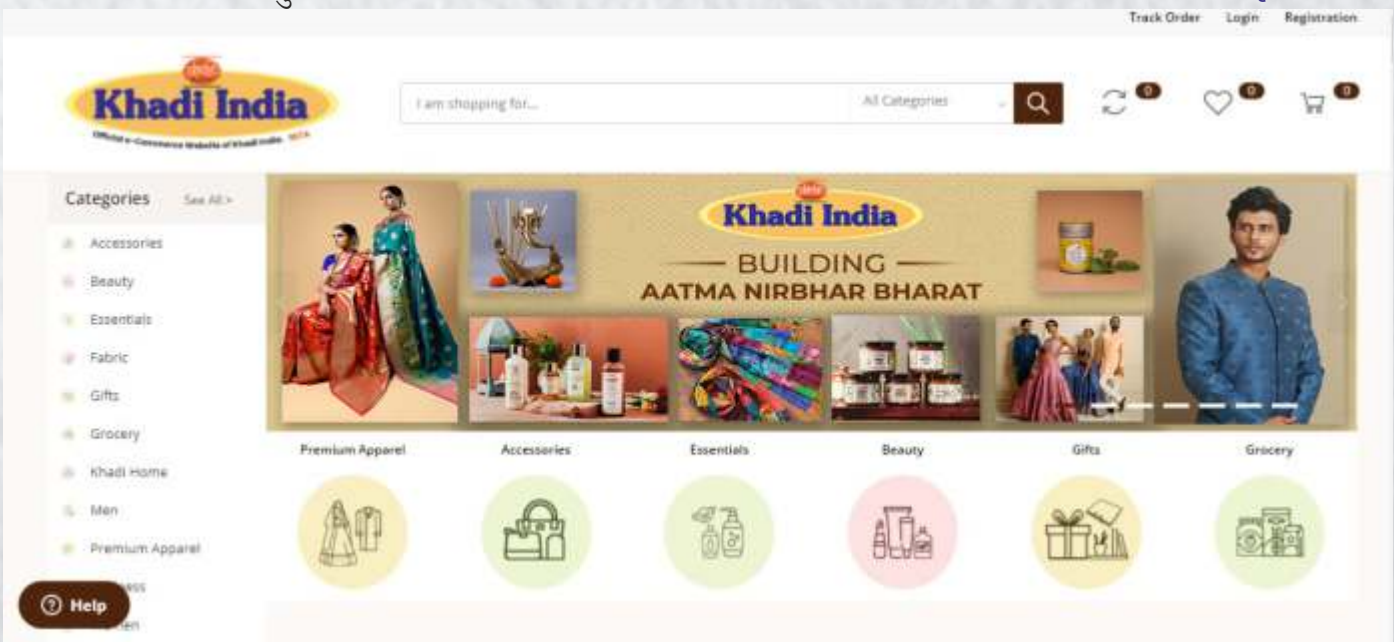

आयोग ने भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

अर्द्धसैनिक बल खादी की दरियों का उपयोग करेंगे

नई दिल्ली, 06.01.2021: गृह मंत्री श्री अमित शाह की अर्द्धसैनिक बलों में एक बड़ा स्वदेशी अभियान चलाने की परिकल्पना को गति देते हुए आज खादी ग्रामोद्योग आयोग और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के बीच अर्द्धसैनिक बलों को खादी कॉटन की दरियों की आपूर्ति करने का एक नया समझौता हुआ। खादी ग्रामोद्योग आयोग ने हर साल 1.72 लाख खादी कॉटन की दरियों की आपूर्ति के लिए आईटीबीपी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

इस समझौता पत्र पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग के उप-मुख्य कार्यकारी अधिकारी और आईटीबीपी के डीआईजी ने खादी ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना और गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव श्री विवेक भारद्वाज तथा केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

यह समझौता एक साल के लिए किया गया है जिसके बाद इसका फिर से नवीकरण किया जाएगा। 1.72 लाख दरियों की कुल कीमत 8.74 करोड़ रुपये है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान पहल के समर्थन के लिए गृह मंत्रालय ने अर्द्धसैनिक बलों को स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित करने का निर्देश दिया था, उसी के संदर्भ में यह समझौता किया गया है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री नितिन गडकरी ने इस कदम का स्वागत किया।

विशिष्ट विवरण के अनुरूप खादी ग्रामोद्योग आयोग 1.98 मीटर लंबी और 1.07 मीटर चौड़ी नीले रंग की दरियों की आपूर्ति करेगा। खादी की इन दरियों को उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के कारीगर तैयार करेंगे। खादी की दरियों के बाद, खादी के कंबल, चादरें, तकिये के कवर, अचार, शहद, पापड़ और प्रसाधन सामग्री जैसे उत्पादों पर भी काम किया जाएगा।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया और कहा कि इससे न सिर्फ हमारे बलों में स्वदेशी उत्पादों को प्रोत्साहन मिलेगा बल्कि खादी कारीगरों के लिए बड़े पैमाने पर अतिरिक्त रोजगार का सृजन भी होगा। श्री सक्सेना ने कहा, "अपने जवानों को सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता वाले उत्पाद उपलब्ध कराना और इनकी समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करना हमारी उच्च प्राथमिकता होगी। केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) से खरीद ऑर्डर मिलना खादी कारीगरों के लिए गर्व का विषय है जो कि देश के जवानों की अपनी तरह से सेवा कर रहे हैं।"

खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने आटीबीपी द्वारा उपलब्ध कराए गए नमूनों के आधार पर इन कॉटन दरियों का निर्माण कराया है और इन्हें एजेंसी द्वारा मंजूरी भी दी गई है। खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा तैयार इन कॉटन दरियों को उत्तर भारत वस्त्र अनुसंधान संगठन (एनआईटीआरए) ने भी प्रमाणित किया है। एनआईटीआरए वस्त्र मंत्रालय का एक यूनिट है और इसे वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग से भी मान्यता प्राप्त है।

इससे पहले, पिछले वर्ष 31 जुलाई को, खादी ग्रामोद्योग आयोग ने आईटीबीपी के साथ कच्ची घानी सरसों तेल की आपूर्ति के लिए भी एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था जिसका सफलतापूर्वक अनुपालन किया गया। आईटीबीपी गृह मंत्रालय द्वारा नियुक्त वह नोडल एजेंसी है जो देश के सभी अर्द्धसैनिक बलों की ओर से सामानों की खरीद करती है।

आयोग द्वारा स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने के लिए पश्चिम बंगाल में 2250 कारीगरों को चरखे, करघे, परिधान मशीनें वितरित

मालदा, 29.01.2021: खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में 2250 कारीगरों को लाभान्वित करते हुए एक व्यापक रोजगार अभियान की शुरुआत की।

राज्य में स्थायी आजीविका के अवसर तैयार करने के उद्देश्य से, केवीआईसी के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने नए मॉडल के 1155 चरखे, 435 सिल्क चरखे, 235 रेडीमेड परिधान बनाने की मशीन, 230 आधुनिक करघे और कारीगरों के परिवारों को 135 रीलिंग बेसिन वितरित किए। लाभार्थियों में लगभग 90 प्रतिशत महिला कारीगर शामिल हैं जो कताई और बुनाई की गतिविधियों से जुड़ी हैं।

इन उन्नत उपकरणों का वितरण हाल के वर्षों में पश्चिम बंगाल में इस तरह के सबसे बड़े अभियानों में से एक है। यह अभियान मालदा में रेशम और सूती उद्योग में कताई, बुनाई और रीलिंग गतिविधियों के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन होगा। केवीआईसी ने मालदा के 22 खादी संस्थानों को मजबूत करने के लिए 14 करोड़ रुपये का वितरण किए हैं। यह अभियान इस जिले में रेडीमेड परिधान उद्योग को भी मजबूत करेगा, जो स्थानीय कारीगरों के लिए आजीविका का एक प्रमुख स्रोत रहा है।

केवीआईसी के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि पश्चिम बंगाल में खादी उद्योग को मजबूत करना प्रधानमंत्री के हर परिवार में एक चरखा होने के सपने के साथ जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि इससे हर हाथ को काम मुहैया कराने के बड़े लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी।

श्री सक्सेना ने कहा, "पश्चिम बंगाल में पारंपरिक कपास और रेशम उद्योग को मजबूत करके राज्य में बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन करने पर केवीआईसी का मुख्य रूप से जोर दे रहा है। बंद इकाइयों को पुनर्जीवित करने, मौजूदा उद्योगों को मजबूत करने और स्थानीय कारीगरों के लिए स्थायी स्थानीय रोजगार सृजित करने से न केवल वित्तीय आत्मनिर्भरता सुनिश्चित होगी बल्कि पश्चिम बंगाल को कपास, रेशम एवं परिधान निर्माण के क्षेत्र में और भी अधिक मजबूत बनाने में मदद मिलेगी।"

केवीआईसी के अध्यक्ष ने कहा कि पश्चिम बंगाल में शुरू की गई रोजगार गतिविधियां "आत्मनिर्भर भारत" और "स्थानीय के लिए मुखर" आह्वान को बढ़ावा देंगी। उन्होंने कहा, "उन्नत मशीन के साथ कारीगरों को सशक्त बनाने से उत्पादन गतिविधियों में तेजी आएगी और अंततः उनकी आय में वृद्धि होगी। यह पश्चिम बंगाल के पुराने शिल्प को पुनर्जीवित करने में एक लंबा रास्ता तय करेगा। यह उल्लेखनीय है कि कई सदियों से, पश्चिम बंगाल कुछ बेहतरीन सूती और रेशमी कपड़े के उत्पादन के लिए जाना जाता है। राज्य व्यापक रूप से अपने मूगा, शहतूत और तसर रेशम के लिए प्रख्यात है, जो पीढ़ियों से एक प्रमुख कारीगरी गतिविधि थी।

राज्य अपने विश्व प्रसिद्ध मुस्लिन कपास के लिए भी जाना जाता है। केवीआईसी ने पहली बार अपने ई-पोर्टल के माध्यम से मलमल कपड़े को ऑनलाइन बिक्री मंच प्रदान किया है, जिसने बंगाल की खादी संस्थाओं को काफी बढ़ावा दिया है। श्री सक्सेना ने संस्थानों से दरियों, कंबल आदि जैसे नए उत्पादों का पता लगाने का भी आग्रह किया, जिसके लिए केवीआईसी को अर्धसैनिक बलों से भारी ऑर्डर मिल रहे हैं।

कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान केवीआईसी को रेलवे के 49 करोड़ रुपये की खरीद के ऑर्डर से खादी कारीगरों को बड़ा प्रोत्साहन

नई दिल्ली, 12.01.2021: पिछला वर्ष कोविड-19 लॉकडाउन के कारण बहुत हद तक प्रभावित रहा, लेकिन भारतीय रेल से प्राप्त 48.90 करोड़ रुपये के बराबर के बड़े खरीद ऑर्डर से पिछले वर्ष खादी गतिविधियों को काफी बढ़ावा भी मिला। जहां रेलवे ने केवल दिसंबर 2020 में ही 8.48 करोड़ रुपये के बराबर के खादी सामानों की खरीद की, इसने कोविड -19 के चुनौतीपूर्ण समय में खादी कारीगरों के लिए पर्याप्त मात्रा में रोजगार और आय का सृजन किया।

भारतीय रेलवे से खरीद के ऑर्डर से देश भर के 82 खादी संस्थानों के साथ पंजीकृत कारीगरों को सीधा लाभ मिला, जो चादर, तौलिया, झंडा बैनर, स्पंज कपड़े, दोसुती कपास खादी, बंटिंग कपड़ों तथा अन्य सामग्रियों के उत्पादन से जुड़े हुए हैं।

भारतीय रेलवे ने मई 2020 से दिसंबर 2020 (21 दिसंबर तक) की अवधि के दौरान 48.90 करोड़ रुपये के बराबर की खादी सामग्रियों की खरीद की, जिसने खादी कार्यकलापों को महामारी के दौरान गतिशील बनाए रखा। दिलचस्प बात यह है कि भारतीय रेलवे ने मई और जून के महीनों में खादी से 19.80 करोड़ रुपये के बराबर के सामान की खरीद की थी, जब लॉकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था को गंभीर क्षति पहुंची थी। इसी प्रकार, रेलवे ने जुलाई और अगस्त के दौरान 7.42 करोड़ रुपये के बराबर के खादी के सामानों की खरीद की थी, जबकि उसने अक्टूबर और नवंबर के महीनों में 13.01 करोड़ रुपये के खादी के उत्पादों की खरीद की।

केवीआईसी के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने केवीआईसी को बड़े ऑर्डर देने के जरिए खादी कारीगरों की सहायता करने के लिए माननीय रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल को धन्यवाद दिया। श्री सक्सेना ने कहा, "महामारी के दौरान केवीआईसी को कारीगरों के रोजगार और आजीविका को बनाए रखने की सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। जहां केवीआईसी ने महामारी के दौरान खादी मास्क बनाने में अपने कारीगरों को लगाया; इसने रेलवे से थोक ऑर्डर भी प्राप्त किए, जिससे खादी का चरखा लगातार चलता रहा। इसका परिणाम कारीगरों के लिए अतिरिक्त रोजगार और आय के रूप में आया, जिसने उन्हें वित्तीय संकट से उबारने तथा देश की अर्थव्यवस्था को समर्थन देने में मदद की।"

सीधी खरीद के माध्यम से खादी की सहायता करने के अतिरिक्त, रेलवे ने खादी कारीगरों को सुदृढ़ बनाने के लिए कई नीतिगत फैसले भी क्रियान्वित किए हैं। इस तरह के एक कदम के रूप में, रेलवे ने 400 रेलवे स्टेशनों को निर्दिष्ट किया है, जहां यात्रियों को भोजन और पेय पदार्थ बेचने के लिए केवल मिट्टी के बर्तन का उपयोग किया जाता है और इस तरह कुम्हार सशक्तिकरण योजना के तहत केवीआईसी द्वारा प्रशिक्षित कुम्हारों को काफी बढ़ावा मिलता है। रेल मंत्रालय अन्य 100 रेलवे स्टेशनों को "प्लास्टिक-मुक्त स्टेशन" के रूप में अधिसूचित करने की प्रक्रिया में है।

लखनऊ में आयोग के अध्यक्ष द्वारा एक बैग निर्माण - पीएमईजीपी इकाई का उद्घाटन

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने लखनऊ में एक गैर-बुने हुए बैग निर्माण - पीएमईजीपी इकाई का उद्घाटन किया, जिसमें स्थानीय 9 व्यक्ति कार्यरत हैं। उभरते उद्यमी स्वरोजगार के माध्यम से रोजगार सृजक बनकर माननीय प्रधान मंत्री के आत्मनिर्भर भारत अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं।

आयोग के अध्यक्ष ने भेलसर में एक पीएमईजीपी इकाई-जनता बेकरी का उद्घाटन किया

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने 24 जनवरी, 2021 भेलसर, अयोध्या, उ.प्र. में एक पीएमईजीपी इकाई-जनता बेकरी का उद्घाटन किया, यह इकाई न केवल स्वादिष्ट बेकरी व्यंजन बनाती है, बल्कि 100 कर्मचारियों के परिवारों को भी खाना खिलाती है। इकाई के मालिक अब्दुल कादिर को केवीआईसी से द्वितीय ऋण के रूप में 70 लाख रुपये राशि की सहायता मिली है। यह इकाई नए उद्यमियों के लिए एक सफल मॉडल है।

राष्ट्रपति भवन में 23.01.2021 को स्थापित नए मधुवाटिका की एक झलक, जहां 2017 में हनी मिशन की शुरुआत हुई थी। भारत के "स्वीट क्रान्ति" की तर्ज पर किए जा रहे प्रयास और भी मधुर परिणाम दे रहे हैं।

आयोग की मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुश्री प्रीता वर्मा ने 7 जनवरी, 2021 को देवास, मध्य प्रदेश में पीएमईजीपी चर्म उत्पाद एवं वस्त्र निर्माण इकाई का उद्घाटन किया।

(पृष्ठ 20 से आगे.....)

ई-मार्केटिंग के जरिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म.....

- विशेषरूप से खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों की बिक्री पर केन्द्रित
- इस पोर्टल पर ग्राहकों के लिए असली खादी ट्रेड मार्क वाले उत्पाद उपलब्ध होंगे
- यह पोर्टल एक ऐसी प्रणाली पर विकसित किया गया है, जहां कोई भी एसएमई/कारीगर/बुनकर अपने उत्पादों को सीधे ग्राहकों तक बेचकर डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है
- ekhadiindia.com वेबसाइट आधुनिक प्रौद्योगिकी पर आधारित होने का दावा करने वाले अन्य ई-कॉमर्स पोर्टल के समान अथवा उनसे एक कदम आगे है।
- इस पोर्टल पर बड़ी मात्रा में ऑर्डर करने और विक्रेताओं के लिए सीधे पंजीकरण करने की सुविधा उपलब्ध है
- केवीआईसी/ केवीआईबी/ पीएमईजीपी/ एसएफयूआरटीआई/ एमएसएमई/उद्यमियों के एकीकरण और केवीआईसी के अंतर्गत काम करते हुए नई एमएसएमई/पीएमईजीपी इकाइयों की सहायता करने वाले सभी हितधारकों के लिए यह एक व्यापक प्लेटफॉर्म है।
- इस पोर्टल पर ग्राहक सुविधा केन्द्र, रिफंड पॉलिसी जैसी तमाम सुविधाएं हैं।
- एक समय में एक साथ 50,000 से भी ज़्यादा ग्राहक इस पोर्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं।
- यह पोर्टल सोशल मीडिया के अनुकूल है।
- वेबसाइट और मोबाइल ऐप दोनों रूप में उपलब्ध है।
- डिजिटल भुगतान की सुविधा।
- करीब 1.2 अरब से ज़्यादा लोगों तक इसकी पहुंच और देश के प्रत्येक हिस्से में उत्पाद पहुंचाने की सुविधा।
- ग्राहकों की ज़रूरत की विभिन्न श्रेणियों को ध्यान में रखते हुए 1500 से ज़्यादा उत्पादों के साथ शुरुआत।

केवीआईसी देशभर में बड़ी संख्या में रोज़गार प्रदान करने वाला संगठन है, जो विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार के माध्यम से प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने में अहम भूमिका निभा रहा है। केवीआईसी खादी और ग्रामोद्योग के साथ मिलकर बुनकरों, कारीगरों, हस्तशिल्पों, किसानों और सूक्ष्म/लघु उद्यमियों के लिए एक नई पीढ़ी के डिजिटल बाज़ार के तौर पर उभरने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने 72 वां गणतंत्र दिवस मनाया

मुंबई: 26 जनवरी, 2021 को खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने 72 वां गणतंत्र दिवस देशभक्ति के साथ मनाया। केवीआईसी की वित्तीय सलाहाकार सुश्री आशिमा गुप्ता ने मुख्य सतर्कता अधिकारी डॉ. संघमित्रा, सं. मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री वाई.के. बारामतीकर एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी उपस्थिति में आयोग मुख्यालय, मुंबई में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर सभी ने भारत के संविधान के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट की।

इस अवसर पर संबोधित करते हुए वित्तीय सलाहाकार महोदया ने भारत के संविधान के महत्व पर प्रकाश डाला और इसकी अद्वितीय विशेषताएं जैसे कि संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य संविधान की प्रस्तावना में निहित हैं। उन्होंने माननीय एमएसएमई मंत्री के मार्गदर्शन में और आयोग के अध्यक्ष के नेतृत्व में केवीआईसी द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न अग्रणी कार्यक्रमों और इसकी उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला और संगठन के लिए और अधिक प्रशंसनीय कार्यों के लिए जन मानस को प्रेरित किया, जिसे सामाजिक आर्थिक तबके के गरीबों के जीवन को छूने के उद्देश्य से शुरू किया गया है।

उन्होंने कहा कि माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्थानीय और आम लोगों के लिए आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल आह्वान के बाद, केवीआईसी ने स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न खादी और ग्रामोद्योग कार्यक्रमों की शुरुआत की है।

भाषण के बाद राष्ट्रगान का गायन किया गया। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों ने भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा कोविड-19 महामारी पर सुरक्षा के लिए जारी किए गए सभी आवश्यक दिशानिर्देशों का पालन करते हुए ध्वजारोहण समारोह में भाग लिया।

बहुउद्देश्यीय प्रशिक्षण केन्द्र, त्रिशुर

आंचलिक/राज्य कार्यालय तथा बहुउद्देश्यीय प्रशिक्षण केन्द्र, बंगलुरु

राज्य कार्यालय, जम्मू कश्मीर

केन्द्रीय पूनी संयंत्र, त्रिचुर

पीएमसी केन्द्र, पंपोर

राज्य कार्यालय, जयपुर

राज्य कार्यालय, देहरादून

विभागीय कार्यालय, मदुरै

महबूबनगर में कुम्हारी चाक के साथ प्रमाण-पत्र का वितरण

कुम्हार सशक्तिकरण कार्यक्रम के तहत 7 जनवरी 2020 को महबूबनगर और नारायणपेठ जिलों में कुम्हारी चाक के साथ प्रमाण-पत्र का वितरण किया गया, जहाँ जिला कलेक्टर, कुम्मारीसंघम के स्थानीय जनप्रतिनिधियों के अलावा कुम्हारी कारीगरों ने भाग लिया। इस अवसर पर आयोग के राज्य निदेशक, तेलंगाना श्री वी. चन्दुलाल उपस्थित थे

आयोग द्वारा खादी प्राकृतिक पेंट बनाने पर प्रशिक्षण हेतु नवोदित उद्यमियों के प्रथम बैच के प्रशिक्षण की शुरूआत

डिस्टेम्पर पेन्ट

इमल्शन पेन्ट

आयोग ने गाय के गोबर से खादी प्राकृतिक पेंट बनाने पर प्रशिक्षण हेतु 21.01.2021 को नवोदित उद्यमियों के लिए प्रथम बैच के प्रशिक्षण की शुरूआत की।

यह नवीन तकनीक हर हाथ को रोज़गार के माननीय प्रधान मंत्री के सपने को साकार करने में मदद करेगी और पुनरुत्थानशील भारत के भविष्य को आकार देगी।

फुटवियर बनाने हेतु प्रशिक्षण एवं प्रमाण पत्र का वितरण

केन्द्रीय फुटवियर प्रशिक्षण संस्थान और खादी और ग्रामोद्योग आयोग के सहयोग से फुटवियर बनाने हेतु एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय प्रधान मंत्री के जन्म दिवस (17.09.2020) पर किया गया था, जिसमें 20 उम्मीदवारों ने भाग लिया जिन्हें दो महीने की अवधि का प्रशिक्षण प्रदान किया गया और जिसका समापन 25.11.2020 को हुआ था। श्री डी.एस. भाटी, निदेशक, केवीआईसी, वाराणसी के साथ श्री गुलाम हुसैन, तकनीकी विशेषज्ञ, पीएमईजीपी द्वारा 19.01.2021 को प्रशिक्षित उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। निदेशक ने उम्मीदवारों को आत्मनिर्भर बनने और दूसरों को रोजगार प्रदान करने के लिए अपनी इकाई स्थापित करने के लिए प्रेरित किया।

कार्यशालाएं

आयोग के गजानन नाईक बहुउद्देश्यीय प्रशिक्षण केन्द्र, दहानू में 20-20 समूह क्षमता के साथ युवाओं के लिए ग्रामीण अभियंत्रण एवं बढईगीरी में एवं 20 युवाओं के लिए अन्य लघु उद्योगों में 6 महीने का छात्रवृत्ति सहित पाठ्यक्रम शुरू किया गया जिसका शुभारंभ अपर जिला अधिकारी, पालघर द्वारा किया गया|

कार्यशालाएं

आयोग के गजानन नाईक बहुउद्देश्यीय प्रशिक्षण केन्द्र, दहानू द्वारा चिंचडी, दहानू जिला पालघर में एक कारीगरों के साथ एक कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें क्षेत्र के संसद सदस्य, जिला अधिकारी, पालघर एवं अन्य अधिकारी भी उपस्थित हुए|

कार्यशाला में खादी और ग्रामोद्योग आयोग की योजनाओं जैसे पीएमईजीपी, स्फूर्ति, केआरडीपी व अन्य योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई, बैठक में खासकर डाई मेकिंग के कारीगरों के साथ चर्चा की गई क्योंकि पूरे भारत में डाई मेकिंग का कार्य केवल दहानु के चिचड़ी क्षेत्र में ही किया जाता है|

यहां लगभग 5000 कारीगर डाई मेकिंग से जुड़े हुए हैं, इस कार्यशाला में 200 स्थानीय कारीगरों ने भाग लिया, जिन्हें स्फूर्ति कलस्टर के तहत कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया गया|

आयोग के गजानन नाईक बहुउद्देश्यीय प्रशिक्षण केन्द्र, दहानू द्वारा गाँव आगर, कोशबड, कंकराडी, दहानू, जिला पालघर में एक 250 कारीगरों के साथ एक अन्य कार्यशाला संपन्न हुई, जिसमें क्षेत्र के माननीय सांसद सदस्य, बचतगट, स्वयं सहायता समूह एवं कई संस्थाओं के सदस्य एवं अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे, कार्यशाला में खादी और ग्रामोद्योग आयोग की योजनाओं जैसे पीएमईजीपी, स्फूर्ति, केआरडीपी व अन्य योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई|

गजानन नाईक बहुउद्देश्यीय प्रशिक्षण केन्द्र, दहानू द्वारा गवर्नमेंट मिडिल आश्रम स्कूल, खंबाले, जिला पालघर में एक जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें बच्चों को ट्रेनिंग और आयोग की स्कीमों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई सभी बच्चे आदिवासी हैं जो 12 वीं क्लास करने के उपरांत कोई ना कोई ट्रेनिंग का लाभ उठा सकते हैं|

उत्तर प्रदेश राज्य में पीएमईजीपी योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने हेतु लखनऊ में राज्य स्तरीय निगरानी समिति की बैठक आयोजित

उत्तर प्रदेश राज्य में पीएमईजीपी योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने के पीएमईजीपी योजना के तहत राज्य स्तरीय निगरानी समिति की बैठक 08.01.2021 को लखनऊ में आयोजित की गई।

बैठक की अध्यक्षता डॉ. नवनीत सहगल, आईएएस, अतिरिक्त मुख्य सचिव, यूपी सरकार ने की। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सभी स्थानीय प्रमुख और यूपी में कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अध्यक्षों, उप महाप्रबंधकों, एसएलबीसी, आयोग के राज्य निदेशक, लखनऊ, मंडलीय निदेशक, गोरखपुर, संयुक्त आयुक्त (उद्योग) और आयोग के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पीएमईजीपी), उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के पदाधिकारियों ने एसएलबीसी बैठक में भाग लिया।

विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, बैठक में भाग लेने वाले बैंकर्स ने फरवरी 2020 तक, पीएमईजीपी के तहत यूपी राज्य को आवंटित वर्ष 2021 के लक्ष्य को शत-प्रतिशत प्राप्त करने का आश्वासन दिया, जोकि संदर्भित मार्जिन मनी दावों को सुधारने और स्वीकृत मामलों के संदर्भ में लबित मार्जिन मनी के दावों को मामलों को मंजूरी दी गयी, ताकि मार्च, 2021 से पहले लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

राज्य कार्यालय, देहरादून में
स्वच्छता पखवाड़ा

आयोग के राज्य कार्यालय, देहरादून में स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान दिनांक 11.01.2021 को नवीन प्रौद्योगिकियों पर वर्चुअल संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी के दौरान श्री नवीन कुमार सदाना, वरिष्ठ प्रबंधक, वेस्ट वॉरियर्स सोसायटी, देहरादून व श्री अजीत तिवारी, परियोजना प्रबंधक, फीडबैक फाउंडेशन चेरिटेबल ट्रस्ट, गुड़गांव ने कूड़ा प्रबंधन के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर उप निदेशक प्रभारी तथा अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया।

राज्य कार्यालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, देहरादून में 4 जनवरी, 2021 से प्रारम्भ स्वच्छता पखवाड़े का समापन उप निदेशक प्रभारी श्री राम नारायण की अध्यक्षता में किया गया।

सोशल मीडिया एवं ई-पेपर

News | FOREVER NEWS | 15-21 January 2021 | 6

Nitin Gadkari Launched Innovative Khadi Prakritik Paint with "Ashta Laabh" in the Lap of the Nature

Veterans Day Wreath Laying Ceremony Held At Naval Dockyard Mumbai

मिलेगा रोजगार | बाराबंकी में लगाया जाएगा प्लांट, ग्रामोद्योग अध्यक्ष ने दी जानकारी

गाय के गोबर से बनेगा पेंट

ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष विनय सक्सेना ने लिया खादी आश्रम का जायजा।

दिन में औसतन 20 से 25 किलो गोबर होती है। इससे पशुपालकों को प्रतिदिन 100 से 125 रुपये तक का लाभ होगा।

जयपुर की कुमारप्पा नेशनल हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट का उत्पादन

जनसंदेश टाइम्स 12/1/2021

अब बाजार में बिकेगा 'गोबर पेंट'

खादी और ग्रामोद्योग आयोग की नई योजना

दिव्यकांत की 10 साल की मेहनत लाई रंग

गाय के गोबर की बनाई इको-फ्रेंडली मूर्तियां

Hindustan Times

BUSINESS | Powered by mint

KVIC launches E-commerce Portal: ekhadiindia.com

MUMBAI: On New Year's eve, Khadi and Village Industries Commission (KVIC) unveils Khadi India's official e-Commerce site eKhadiIndia.com. The website catalogues over 50,000 products under more than 500 varieties and various categories of locally made Khadi and Village Industries products. The portal is a step towards building an ecosystem that enables MSMEs to help achieve the Prime Minister's goal of "Aatmanirbhar Bharat". KVIC Chairman Vinai Kumar Saxena during the launch function informed that ekhadiindia.com is the first of its kind government online shopping platform to boost rural economy and become self-sustainable. There has been a steady rise in demands for Khadi and Village Industries products over the last few years with 2018-2019 alone witnessing the surge of 25%. The products range from apparel, grocery, cosmetics, home décor, health and wellness products, essentials and gifts. NT

जौनपुरियों ने की 72.46 लाख की खरीदारी

जौनपुर। खादी और ग्रामोद्योग आयोग (भारत सरकार) द्वारा आयोजित 15 दिवसीय राज्य स्तरीय खादी प्रदर्शनी का आयोजन दिनाँक 10.01.2021 से 25.01.2021 तक बी. आर. पी. इंटर कालेज मैदान जनपद में किया गया है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मण्डलीय कार्यालय, तेलियाबाग, वाराणसी के निदेशक डी. एस. भाटी ने प्रदर्शनी की समीक्षा बैठक के उपरान्त बताया कि जौनपुर के खादी प्रेमियों द्वारा दिखाया गया खादी के प्रति रुझान में दिनाँक 10.01.2021 से दिनाँक 16.01.2021 तक रु. 72.46 लाख तक की रिकार्ड बिक्री दर्ज की गई है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग (खादी प्रदर्शनी) जौनपुर में खादी प्रेमियों का आभार व्यक्त करती है तथा आगामी शेष सप्ताह में जौनपुर जनपद के खादी प्रेमियों से यह भी अपील करती है कि खादी के प्रति अपने रुझान को बरकरार रखते हुए स्वयं अधिक से अधिक खादी एवं ग्रामोद्योगी वस्तों की खरीद करें जिससे कि खादी से जुड़े देश के कत्तिनों बुनकरों एवं कारिगरों को अधिक से अधिक रोजगार मुहैया कराया जा सके। इस प्रदर्शनी एवं जौनपुर निवासियों के खादी प्रेम को देखते हुए सभी संस्थाएँ अति प्रसन्न हैं।

लोकसत्ता

खादीला 'ई-पेंट'चा आधुनिक साज

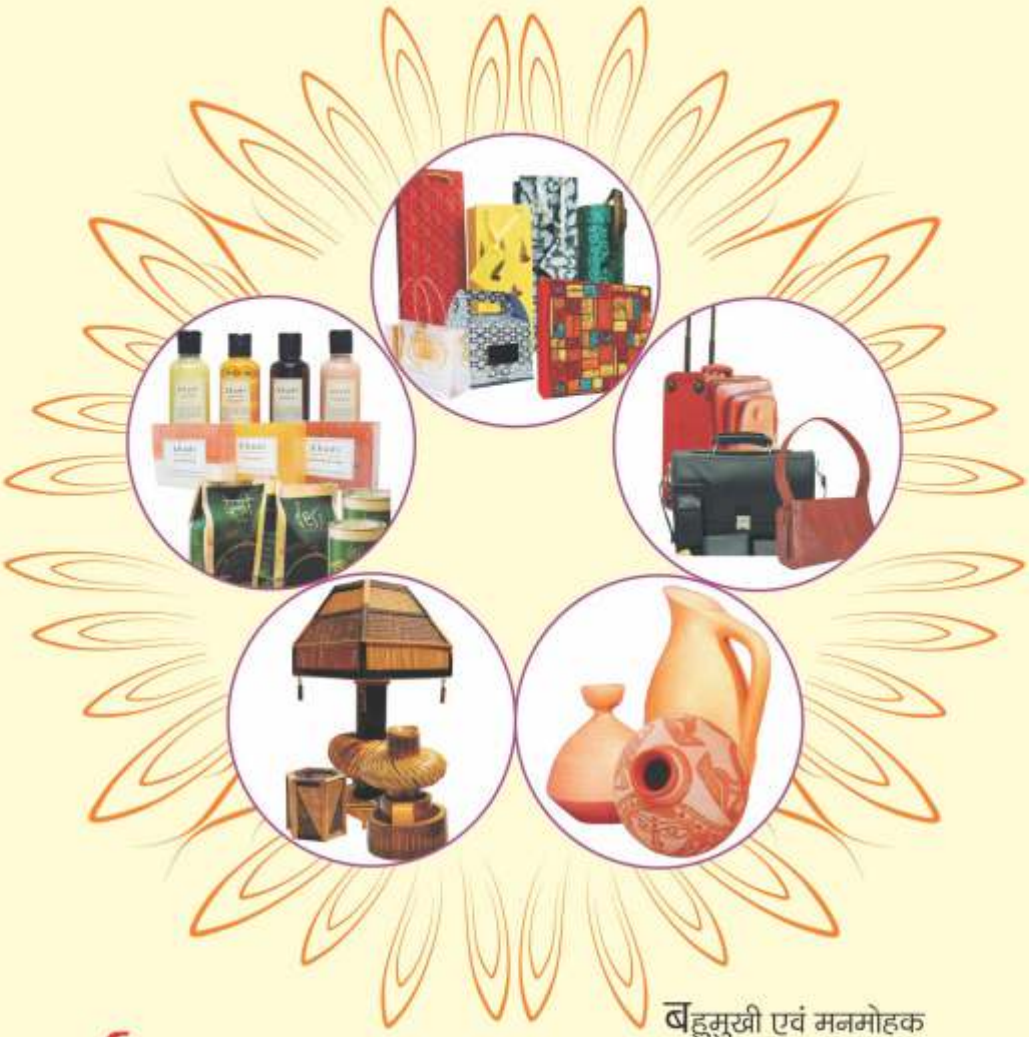

पर्यावरणानुकुल उत्पादों का एक स्थान

बहुमुखी एवं मनमोहक
खादी डिजाइनर परिधानों
जैसे पर्यावरणानुकूल उत्पादों का एक स्थान
खादी वस्त्र, हर्बल उत्पाद,
रसायन रहित अगरबत्तियां,
विषाणु रहित एवं एन्टी फंगल शहद,
नैसर्गिक एवं आयुर्वेदिक सौन्दर्य उत्पाद
जैसे साबुन एवं शैम्पू,
हाथ कागज एवं पारंपरिक हस्तशिल्प
तथा अन्य उत्पादों की विशाल श्रृंखला

खादी और ग्रामोद्योग आयोग
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार
ग्रामोदय, 3, इर्ला रोड़, विले पार्ले (पश्चिम), मुम्बई-400 056.
वेबसाईट : www.kvic.org.in

खादी
Khadi India

"भारत में हम रोजगार सृजन करते है तथा समृध्दि बुनतें हैं"